आर.एन.आई. पंजीयन क्र. 39596/82 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)

साप्ताहिक

मालव अँचल

वर्ष 47 अंक 23 (प्रति रविवार) इंदौर, 25 फरवरी से 02 मार्च 2024 पृष्ठ-8 मूल्य 3 रुपये

प्रधानमंत्री मोदी ने 41 हजार करोड़ लागत की रेल परियोजनाएं राष्ट्र को की समर्पित

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधुनिक और तेज रेलवे के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 41 हजार करोड़ की लागत से देश के 554 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प और 1500 रोड ओवर ब्रिज-अंडरपास के शिलान्यास, उद्घाटन समर्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सीहोर से शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के 33 से अधिक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार माना। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में 77 हजार करोड़ रुपए के निर्माण कार्य जारी हैं, प्रदेश में रेलवे सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है, और हमें नई तकनीक और नई व्यवस्थाओं के साथ विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन एवं रेल सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सीहोर जिले की जन आभार यात्रा में शामिल हुए। केन्द्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित किया।

इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, खंडवा, सीहोर सहित प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्विकास

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास परियोजनाओं की शिलापट्टिकाओं का अनावरण किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश के 33 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शिलान्यास के साथ ही 133 रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) एवं अंडरपास का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। प्रदेश के जिन 33 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास के लिए शिलान्यास किया गया, उनमें सीहोर, जबलपुर, बीना, अशोकनगर, खिरकिया, साँची, शाजापुर, ब्यौहारी, बरगवाँ, नरसिंहपुर, पिपरिया, इन्दौर, उज्जैन, मंदसौर, मक्सी, नागदा, नीमच, शुजालपुर, खाचरोद, बालाघाट, छिंदवाड़ा, खण्डवा, मंडला फोर्ट, नैनपुर, सिवनी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, बिजुरी, मुरैना, हरपालपुर, दतिया और भिंड स्टेशन शामिल हैं।

भोपाल-सीहोर-रायसेन, भोपाल-विदिशा, उज्जैन-इंदौर और उज्जैन-देवास ट्विन सिटी के रूप में विकसित होंगे- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उद्योग, रोजगार में बढ़ोत्तरी के साथ ही महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्ग की प्रगति के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। किसी भी योजना के लिए धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी। सीहोर नगर पालिका द्वारा उनके सम्मुख रखे गए प्रस्तावों को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि भोपाल और सीहोर का विकास समन्वित रूप से ट्विन सिटी के आधार पर होगा। दोनों नगरों को जोड़कर आवागमन के साधन, आवासीय परियोजनाएं और रोजगार के अवसरों के समग्र विकास की योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। उज्जैन-इंदौर, उज्जैन-देवास, भोपाल-विदिशा, भोपाल-सीहोर-रायसेन जिले अमृत काल में 2047 तक ट्विन सिटी के रूप में विकसित किए जाएंगे।

गजल गायक पंकज उधास का 72 साल की उम्र में निधन

मुंबई । मशहूर गजल गायक पंकज उधास का सोमवार को 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन की जानकारी उनकी बेटी नायाब ने सोशल मीडिया पर दी है। गजल गायक पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। पंकज उधास को बड़ी पहचान फेमस गजल चिट्ठी आई है से मिली थी। पंकज उधास का जन्म 17 मई 1951 को गुजरात के जेतपुर में हुआ था। वो अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे। उनका परिवार राजकोट के पास चरखाड़ी नाम के एक कस्बे का रहने वाला था। उनके दादा जमींदार थे और भावनगर राज्य के दीवान भी थे। उनके पिता केशुभाई उधास सरकारी कर्मचारी थे, उन्हें इसराज बजाने का बहुत शौक था। वहीं उनकी मां जीतूबेन उधास को गानों का बहुत शौक था। यही वजह थी पंकज उधास समेत उनके दोनों भाइयों का रुझान संगीत की तरफ हमेशा से रहा।

2029 तक देश में हो सकते हैं एक साथ चुनाव

सरकार गिरने पर यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी, लॉ पैनल संविधान में जोड़ेगा नया चैप्टर

नई दिल्ली । वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर लॉ पैनल संविधान में एक नया चैप्टर जोड़ सकता है। इसके जरिए आयोग 2029 तक देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश कर पाएगा। सूत्रों की माने तो जस्टिस (रिटायर्ड) रितुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग एक साथ चुनावों पर नया चैप्टर जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा। इस चैप्टर में क्या है, इसकी जानकारी अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन इसी के आधार पर अगले पांच सालों में तीन चरणों में विधानसभाओं को एक साथ लाने की योजना है। जिससे पहला एक साथ चुनाव मई-जून 2029 में हो सके। तब देश में 19वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं। सरकार गिरने पर यूनिटी गवर्नमेंट के गठन की सिफारिश- संविधान के नए अध्याय में एक साथ चुनाव, एक साथ चुनावों की स्थिरता और लोकसभा, विधानसभाओं, पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए सामान्य मतदाता सूची से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे। यदि कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर जाती है या त्रिशंकु सदन होता है, तो आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ यूनिटी गवर्नमेंट के गठन की सिफारिश करेगा। यदि यूनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मूला काम नहीं करता है, तो कानून पैनल सदन के शेष कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश करेगा। सूत्रों ने बताया कि यूनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मूला फेल होने के बाद नए चुनावों की आवश्यकता है। अगर सरकार के पास अभी भी तीन साल हैं, तो स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव बचे हुए कार्यकाल (तीन साल) के लिए होने चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अगुआई में 8 मेंबर की कमेटी- विधि आयोग के अलावा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति भी एक रिपोर्ट पर काम कर रही है कि कैसे संविधान और मौजूदा कानूनी ढांचे में बदलाव करके लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं।

कहीं दोस्ती, कहीं तकरार, इंडिया गठबंधन में चल रही यही रार

नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं में भी कनफ्यूजन

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव करीब हैं, विपक्षी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की गाड़ी भी फुल स्पीड से दौड़ रही है। यूपी, हरियाणा, गुजरात और गोवा के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ में इंडिया में शामिल कांग्रेस और अन्य घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है। लेकिन कुछ राज्य हैं, जहां इंडिया गठबंधन के दो घटक दल आमने-सामने हैं। कुछ राज्यों में कनफ्यूजन की स्थिति भी है।

कांग्रेस और आप के बीच पांच राज्यों में गठबंधन का ऐलान हो गया है। दिल्ली और चंडीगढ़ के साथ ही हरियाणा, गोवा और गुजरात में ये दोनों दल गठबंधन कर चुनाव लड़ने को तैयार है। लेकिन पंजाब में दोनों ही दल एक-दूसरे को चुनौती देना चाहते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन की भी नजर आ रही है। कांग्रेस और लेफ्ट बिहार से लेकर बंगाल तक मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं, जबकि केरल में जहां लेफ्ट की सरकार है, वहां दोनों ही दलों के नेता और उम्मीदवार एक-दूसरे को पटखनी देने के लिए जोर लगाते दिखा रहे है। तृणमूल कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। टीएमसी और कांग्रेस के बीच पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत फिर से बेपटरी होती दिख रही है। मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि हम अकेले ही चुनाव मैदान में उतर रहे है। टीएमसी पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मेघालय सहित नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और उत्तर प्रदेश में अपने लिए सीट भी चाह रही है। चर्चा है कि यूपी में टीएमसी अपने प्रवक्ता ललितेश पति त्रिपाठी के लिए एक सीट चाह रही है। कहीं साथ, कहीं खिलाफ की सियासत से न सिर्फ जनता, बल्कि राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए भी कनफ्यूजन की स्थिति बनने का खतरा है। यह खतरा भी होगा कि कहीं इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेता विरोधियों को अपने ही खिलाफ हमले का हथियार न दे बैठें।

राहुल को वायनाड में ये महिला नेता देगी टक्कर

तिरुवंतपुरम। केरल में भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की सीट वायनाड सहित चार सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की सरकार है। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी का उसका हिस्सा है। वायनाड सीट से पार्टी ने सीपीआई नेता एनी राजा पर भरोसा जताया है। वह राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में टक्कर देती नजर आएंगी। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि केरल में एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीफ में ही मुकाबला होता है।

संपादकीय

कपड़ों की तरह नियम बदल देती है सरकार और संस्थाएं

नियम कायदे कानून यदि कपड़ों की तरह बार-बार बदले जाएं, तो उन नियम और कानून का क्या मतलब रह जाएगा।इसको आसानी के साथ समझा जा सकता है। नर्सिंग के लाखों छात्रों का भविष्य पिछले कई वर्षों से सरकार के नियम कायदे कानून के कारण अटका हुआ पड़ा है। हाईकोर्ट, सीबीआई, विश्वविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियम और कानून के कारण छात्र भटक रहे हैं। किसी छात्र के 2 साल बर्बाद हो गए। किसी छात्र के 3 साल बर्बाद हो गए। केरियर बनाने के लिए उसके हजारों रुपए हर महीने खर्च हो रहे हैं। हर संस्था के अलग-अलग नियम और कानून के इस मकडजाल में फंसकर छात्र छात्राएं परेशान होकर यहां से वहां घूम रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए नियम बदल दिए हैं। पहले 23000 वर्ग फुटफुट पर नर्सिंग कॉलेज के भवन बनाने का नियम था। अब सरकार ने इसे घटाकर 8000 वर्ग फुट कर दिया है। सरकार ने यह नियम नर्सिंग कॉलेज में पाठ्यक्रम सही तरीके से संचालित हो। बिना भवन के जो नर्सिंग कॉलेज चल रहे थे।उन नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी जा सके।इसके लिए सरकार ने नियम बदल दिए हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा नर्सिंग कॉलेज के लिए जो नियम सुनिश्चित किए गए थे। उसे दरकिनार करते हुए सरकार ने नियमों को बदल दिया है। नियम और कानून के इतने सारे मकड़जाल हैं, कि इससे निकाल पाना जो फस गया उसके लिए संभव नहीं है। राजनीतिक समीकरणों तथा नियमों की आड़ में भ्रष्टाचार करने के लिए हर संस्था अपने-अपने नियम कानून बना लेती है। नर्सिंग कॉलेज के मामले में इंडियन नर्सिंग काउंसिल के जो प्रावधान है। उसका पालन सरकार,सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेज संचालकों को करना होता है। जैसे नियम होते हैं, उसके अनुसार कागज बना लिए जाते हैं। जिनके ऊपर जांच करने की जिम्मेदारी होती है। वह अपना शुकराना लेकर आंख बंद कर लेते हैं। वास्तविक स्थिति उसके विपरीत होती है। पिछले कई वर्षों से म. प्र.हाई कोर्ट में यह मामला चल रहा है. छात्र-छात्राओं की परीक्षाएं नहीं हुई हैं। सीबीआई की जांच चल रही है। मनमाने तरीके से नर्सिंग कॉलेज से पैसे लेकर कॉलेज को अनुमति दी गई। अनुमति देते समय किसी भी संस्था ने नियमों का ध्यान नहीं रखा। सारी संस्थाएं मिलजुल कर भ्रष्टाचार का खेल करते हैं। इसमें नुकसान उन छात्र-छात्राओं का हो रहा है। जिन्होंने नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश लिया है ।अभी तक उन्हें नौकरी मिल जानी चाहिए थी प्रदेश और देश में नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी है। कोई भी संस्था एक दूसरे के नियमों के अनुरूप नियम और कानून नहीं बनाते हैं। जिसके कारण यह अव्यवस्था दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। कायदे से नर्सिंग काउंसिल द्वारा जो नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं। उनके अनुसार ही सरकारों, विश्वविद्यालयों और राज्यों की नर्सिंग काउंसिल के कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी रहती हैं। राज्य सरकार, विश्वविद्यालय एवं स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा जो भी नियम बनाए जाएं। उसमें इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियम और दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य है। लेकिन हर संस्था अपने हिसाब से नियम कायदे कानून को समय-समय पर बदलती रहती है। जिसके कारण भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। छात्रों की शिक्षा में एकरूपता और गुणवत्ता नहीं होती है। भ्रष्टाचार की गंगा बहती रहती है। जिसने भ्रष्टाचार की गंगा में नहा लिया, उसके सारे पाप कट जाते हैं। जो नहीं नहा पाता है, वह भटकता रहता है। नर्सिंग के छात्र-छात्राओं का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के पाप ढोने पड़ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से हाईकोर्ट, सीबीआई, नर्सिंग काउंसिल, राज्य सरकार और नर्सिंग कॉलेज के चक्कर लगाने ,भगवान को याद करते हुए, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। लाखों छात्रों का भविष्य खराब हो चुका है।ऐसी स्थिति में न्याय पालिका से यह अपेक्षा की जाती है, कि वह ऐसा निर्णय दे। जिससे इस तरीके की मनमानी खत्म हो सके। नियम कायदे कानून बनाने और उनका पालन किस तरह किया जाएगा। इसकी स्पष्ट गाइडलाइन हो। नियम और कानून बनाने वालों की जिम्मेदारी तय हो। जिन अधिकारियों ने लापरवाही और गड़बड़ी की है। उनको दंडित किए जाने की व्यवस्था हो। तभी जाकर स्थितियों को बेहतर बनाया जा सकता है।जिस तरह से नियम और कानून बनाए जा रहे हैं। थोड़े-थोड़े समय में उनमें बदलाव किए जा रहे हैं। यही भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी गंगोत्री है।

मोदी के तीसरे कार्यकाल की सुखद आहट

ललित गर्ग

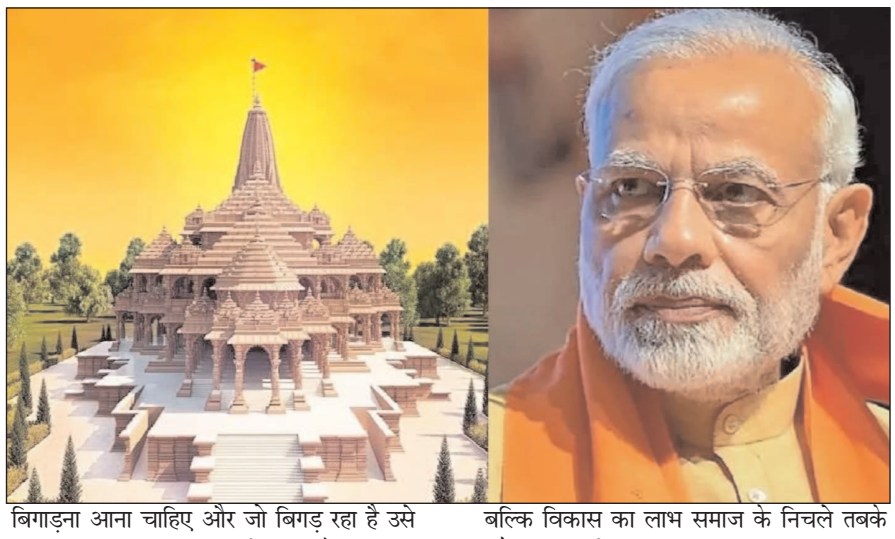

वर्ष 2024 के आम चुनाव सन्निकट हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक एवं धमाकेदार जीत के प्रति आश्वस्त है। एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी एक नयी पारी की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी का यह तीसरा कार्यकाल अगले एक हजार वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल होगा। इस अवधि में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के साथ विश्वगुरु भी बन सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी के दो कार्यकाल की समीक्षा करें तो स्पष्ट हो जाता है कि उनकी सरकार द्वारा उठाये गये हर कदम एवं उनकी हर बात राष्ट्र निर्माण की दिशा में बढ़ाये गये अनूठे, परिवर्तनकारी एवं सकारात्मक कदम रहे हैं। 2014 से पहले के भारत में भ्रष्टाचार, घोटालों और तुष्टिकरण की ही बात सामने आती थी लेकिन अब विकास, अविष्कार और नवाचार की बातें हो रही हैं, जिनमें नये भारत, सशक्त भारत की जड़े गहरी हुई है। मोदी के नेतृत्व में पिछले दस वर्ष भारतीय इतिहास में सबसे सुदृढ़ एवं युगांतरकारी रहे हैं। हम सब इतिहास के उस स्वर्णिम काल के गवाह बनने के साक्षी बने हैं। यह सब मोदी के करिश्माई एवं चमत्कारी व्यक्तित्व से ही संभव हो पाया है। करिश्मा किसी व्यक्ति विशेष का एक निश्चित गुण होता है जो अपवाद होता है और जिसके आधार पर वह स्वीकार्यता हासिल कर शासन करता है। लिंकन, चर्चिल, रूसवेल्ट और जॉन एफ केनेडी महान राजनेता थे, जो अपने करिश्माई व्यक्तित्व और प्रभामंडल के लिए जाने जाते थे और इसका उपयोग उन्होंने अपने देश को मजबूत करने के लिए किया। मोदी इसी श्रेणी के इन सबसे आगे निकलते हुए विलक्षण क्षमताओं एवं मौलिक विशेषताओं वाले विरल नेता है।

2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा एवं सभी विपक्षी दल अपनी-अपनी चालें चल रहे है। भाजपा एवं इंडिया गठबंधन दोनों ही खेमों में अब हर दिन चुनावी रणनीति को लेकर नये गठबंधन हो रहे हैं तो बने हुए गठबंधन टूट रहे हैं, अनेक नेता दलों के पाले बदल रहे हैं, एक दूसरे को मात देने का दौर चल रहा है, सब अपनी-अपनी व्यूह रचना बना रहे हैं। भाजपा ने स्वयं की 370 एवं उसके गठबंधन की 400 सीटों का लक्ष्य बनाया है। इंडिया गठबंधन एवं विभिन्न राजनीतिक दल भी जीत की संभावनाओं को लेकर जुटें हैं। राजनीति पल-पल नया आकार लेती है, इसलिये राजनीति में सही वक्त पर सही ढंग से इस्तेमाल करने का हुनर होना अपेक्षित होता है, जो अच्छा चल रहा है उसे बिगाड़ना आना चाहिए और जो बिगड़ रहा है उसे सुधारना आना चाहिए। इसी को कहते है राजनीति। इसी राजनीति के महारथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा की रणनीति तीक्ष्ण एवं प्रभावी बनकर सामने आ रही है ताकि धमाकेदार चुनाव परिणाम तक पहुंचा जा सके। मोदी के करिश्माई राजनीति का ही परिणाम है कि नीतीश कुमार और जयंत चौधरी जैसे नेताओं को इंडिया गठबंधन से छीन लिया गया है। कांग्रेस के अशोक चव्हान को भाजपा में शामिल करके राज्यसभा में भेजा दिया है। कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की स्वर सुनाई दे रहे हैं। मायावती और चंद्रबाबू नायडू को विपक्ष में जाने से रोक दिया गया है। शिवसेना और राकांपा की दो फाड कर दी गयी है। श्रीराम मन्दिर उद्घाटन से हिन्दू वोटों को प्रभावित किया गया है, वही 'भारत रत्न' की घोषणा से आम चुनावों को प्रभावित करने का राजनीतिक कौशल सामने आया है।

मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व का ही परिणाम है कि आगामी चुनावों में भाजपा की शानदार जीत के बनते दृश्यों को देखकर समूचा विपक्ष बौखलाया हुआ या किंकर्तव्यविमूढ़ दिखाई दे रहा है। यह स्थिति बनने का मूल कारण जहां मोदी का ऐतिहासिक एवं सफल दो कार्यकाल हैं, वही आगामी चुनाव को लेकर उनकी रणनीति एवं राजनीतिक कौशल है। मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व की विशेषताओं में प्रमुख हैं कि वे दूरदृष्टि रखते हैं, लक्ष्य तय करते हैं और उस लक्ष्य को पूरा करने में लगे रहते हैं। वे अपने एजेंडे को लेकर निर्णायक और स्पष्ट हैं। लक्ष्य को हासिल करने के लिए वह अपने भीतर देखते हैं एवं जनता से सीधा संबंध स्थापित करते हैं। उन्होंने सिर्फ भौतिक-आर्थिक विकास के संदर्भ में ही विकास की बात नहीं की बल्कि विकास का लाभ समाज के निचले तबके और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिये योजनाएं एवं नीतियां बनाई ताकि उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आए और अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बने। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्र के सांस्कृतिक पुनरुद्धार को बल दिया, जो सकारात्मक सभ्यता के साझा मूल्यों और इन मूल्यों में गर्व की भावना पर आधारित हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राजनीतिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में देश के लिए एक उचित स्थान बनाया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पास एक सुस्पष्ट दृष्टि है कि आजादी के 75वें या 100वें साल में राष्ट्र किस मुकाम पर होगा। उन्होंने भारत के लिए एक विजन और दीर्घकालिक लक्ष्य तय किया है। इसे हासिल करने के लिए उन्होंने व्यापक लक्ष्य को विभिन्न माध्यमों से दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों में विभाजित किया है और इसमें सरकार के हर वर्ग, पहलू और क्षेत्र को समावेश किया है। लक्ष्य चाहे दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का हो या फिर व्यवसाय की सुगमता का या फिर वैश्विक निर्यात का प्रतिशत या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हिस्सा बढ़ाने का हो, इनके बारे में एक स्पष्ट रुख अख्तियार किया गया है और इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में प्रयास भी चल रहे हैं। आर्थिक और वित्तीय मानदंडों पर भारतीय अर्थव्यवस्था आज सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। इसकी विकास की दर आठ प्रतिशत के इर्दगिर्द घूम रही है। प्रधानमंत्री अपने प्रत्येक संबोधन में देश की हर छोटी बड़ी सफलता का श्रेय 140 करोड़ भारतीयों को देते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश और समाज के जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां विकास की गति को बल न मिल रहा हो। कोरोना काल खंड हो या कश्मीर में 370 को हटाना या फिर यूक्रेन संकट या फिर अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी पर हर जगह भारत की विदेश नीति की कुशल छाप दुनिया में देखी जा रही है।

प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी की तीन विशेषताएं है। एक, ये ईमानदार हैं। दूसरे, योग्य है, और तीसरे, मेहनती है। निश्चित रूप से उनकी वित्तीय ईमानदारी में आज तक किसी को शक नहीं रहा। उनके कट्टर से कट्टर विरोधी भी उनके व्यक्तिगत रूप से बेईमान होने का संदेह व्यक्त नहीं करते। जहां तक उनकी योग्यता एवं दूरदर्शिता का सवाल है, शायद वे अब तक जितने भी प्रधानमंत्री भारत में हुए हैं उनमें इस दृष्टि से सबसे ज्यादा दूरदर्शी हैं। उनके मेहनती होने के बारे में बताया जाता है कि वे 73 साल की उम्र होने के बावजूद, सोलह सोलह घंटे काम करते हैं। कह सकते हैं कि किसी देश को इससे बेहतर प्रधानमंत्री और क्या मिल सकता है, जिसमें ये तीन-तीन दुर्लभ गुण हो? कह सकते हैं कि मुश्किल से ही किसी मुल्क को मिलता है ऐसा प्रधानमंत्री। लेकिन ऐसे योग्य, कर्मठ, विजनरी, ईमानदार प्रधानमंत्री ने आज देश की दशा और दिशा बदल कर रख दी है।

आर्थिक उदारीकरण से पहले श्रमिकों कामगारों को जो अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थीं, उसमें काफी सुधार आया है। खेती-किसानी के लिए कमजोर रूप से किसान को 6000 रुपये की वित्तीय सब्सिडी मोदी सराकार द्वारा दी जा रही है। विदेशी पूंजी का निवेश हो रहा है। सेंसेक्स अभी तक का सबसे उच्चतम स्तर पर जा चुका है। रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक व खेलों की दुनिया में भी भारत का अद्भुत विकास हुआ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज योग पूरी दुनिया में छा गया है और यह उन्हीं के प्रयासों का परिणाम रहा कि आज पूरा विश्व हर वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। योग दिवस की ही तरह विश्व अहिंसा दिवस को भी दुनिया ने स्वीकार कर शांतिपूर्ण एवं अहिंसक जीवनशैली को बल दिया है। आयात से अधिक निर्यात हो रहा है। कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी अच्छे से संचालन कर पा रहे हैं। उसकी विशेषता रही है कि वैश्विक आर्थिक मंदी का उस तरह इस देश को सामना नहीं करना पड़ा जिस तरह से आज पश्चिमी देश मंदी का सामना कर रहे हैं।

एक बड़ा गुण निश्चित रूप से प्रधानमंत्री में होना चाहिए, वह है जनता से जुड़ाव। मौजूदा प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में सर्वाधिक जनता से संवाद कायम किया है और अब तक के सारे मिथ तोड़ दिये हैं।

बिजली सेवाएं समय पर देने के लिए अधिकारी तत्परता से कार्य करें : तोमर

इंदौर। बिजली सेवाओं को समय पर देना ऊर्जा विभाग एवं बिजली वितरण कंपनी का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति में कोई भी लापरवाही न बरतें। सभी जिलों के अधिकारी इस बारे में गंभीरता रखे, समय पर सेवाओं प्रदान करने की सतत् समीक्षा की जाएगी।

मप्र पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी इन्दौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने ये निर्देश दिए। तोमर सोमवार को पोलोग्राउंड स्थित सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। तोमर ने कहा कि सीएम हेल्प लाइन, 1912, कंपनी के पोर्टल, ऊर्जस एप व अन्य माध्यमों से सेवाओं को चाहने वाले एवं शिकायत करने वालों का समय पर समाधान किया जाए। तोमर ने कहा कि फेल ट्रांसफार्मर नियमानुसार एवं पात्रतानुसार समय पर बदले जाए, लाइन लॉस घटाने के लिए सघन प्रयास करें। तोमर ने राजस्व संग्रहण समय पर करने के लिए दैनिक समीक्षा करने के निर्देश दिए। प्रबंध निदेशक तोमर ने कहा कि गर्मी का दौर प्रारंभ हो रहा है, पेयजल आपूर्ति वाले कनेक्शनों की बिजली आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए, वहां कोई मैंटेनेंस कार्य की जरूरत हो तो उसे समय पर किया जाए। इस दौरान मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य, निदेशक पुनीत दुबे, सचिन तालेवार, कार्यपालक निदेशक गजरा मेहता, मुख्य अभियंता एसआर बमनके, रवि मिश्रा, एसएस करवाड़िया, एसआर सेमिल, गिरीश व्यास, आरके आर्य, मुख्य वित्त अधिकारी नरेंद्र बिवालकर, अधीक्षण अभियंता सूचना प्रौद्योगिकी सुनील पाटौदी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता आरके नेगी, संयुक्त सचिव तरूण उपाध्याय आदि ने विचार रखें।

शासन से मंजूरी के लिए अटकी वन टाइम सेटलमेंट योजना

नगर निगम को मिल सकती है जलकर की 350 करोड़ से भी अधिक की राशि

इंदौर। नर्मदा का पानी पीकर लाखों रुपए की धनराशि बकाया करने वालों से वसूली करने की वन टाइम सेटलमेंट योजना को मूर्त रूप नहीं हो मिल सका है। बताया जा रहा है कि इस योजना को शासन स्तर से मंजूरी नहीं मिली है। यदि यह योजना शुरू हो जाती तो हो सकता है निगम के साढ़े 800 करोड़ से भी ज्यादा के बकाया में से अधिकतम निगम के खजाने में आ जाता और निगम की कंगाली दूर हो सकती थी। फिर कुछ भी हो अब निगम को जलकर की बकाया राशि वसूलने के लिए अन्य कोई रास्ता अपनाना पड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार वन टाइम सेटलमेंट योजना को शासन से मंजूरी नहीं मिल सकी है। हालांकि इस योजना का निगम ने भरपूर प्रचार प्रसार भी किया था। बताया तो यह भी जाता है कि सैकड़ो बड़े करदाता जिनके ऊपर लाखों का जलकर बकाया है वह इसमें सेटलमेंट करने की तैयारी में भी रहे लेकिन योजना शुरू ही नहीं हो सकी। बताया जा रहा है कि निगम अधिकारियों ने योजना को पर्याप्त रूप से बनाकर शासन को मंजूरी के लिए भेजा था। वैसे निगम अधिकारियों द्वारा जलकर और संपत्ति करके अलावा अन्य कारों की वसूली में भी भारी लापरवाही की जाती रही है इस कारण भी निगम का करोड़ों रुपया बकाया रह जाता है।

850 करोड़ से ज्यादा का बकाया है जलकर– निगम अधिकारियों की माने तो नगर निगम को नलों से प्रदाय किए जाने वाले नर्मदा के पानी का करोड़ों रुपया लोगों से वसूलना है। यह राशि का आंकड़ा 850 करोड़ से भी अधिक है। अगर वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू हो जाती तो हो सकता है कि निगम के खजाने में 350 करोड़ से अधिक की धनराशि आ जाती। इस राशि से फिलहाल निगम कुछ समय तक तंगहाली से दूर हो सकता था?। मामले में नगर निगम अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने बताया कि शासन द्वारा योजना के संबंध में कुछ क्यूरी की गई है हमने उसका जवाब भी दे दिया है। अब फैसला शासन को ही करता है।

फाग गीतों पर जमकर झूमे सीनियर सिटीजन

इंदौर। गिरिराज माहेश्वरी मित्र मंडल द्वारा गुमाश्ता नगर स्थित मुकूट मांगलिक भवन में फाग महोत्सव आयोजित किया गया। फाग महोत्सव में सभी सिनीयर सिटीजन ने फूलों से होली खेल सभी सदस्यों को पानी बचाने का संदेश दिया। महोत्सव के दौरान ख्याति प्राप्त भजन गायकों ने भजनों की प्रस्तुति से सभी श्रोताओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के पूर्व वरिष्ठ समाजसेवियों का सम्मान भी इस अवसर पर किया गया।

गिरिराज माहेश्वरी मित्र मंडल से जुड़े सुरेश मंडोवरा ने बताया कि फाग महोत्सव की शुरूआत सुधा राठी एवं गोदावरी राठी द्वारा महेश वंदना की प्रस्तुति के साथ की गई। इसके पश्चात माहेश्वरी सामाजिक पारमार्थिक सेवा समिति संस्थापक अध्यक्ष डॉ. रविन्द्र राठी एवं विशेष अतिथि इन्दौर जिला माहेश्वरी समाज प्रचार मंत्री अजय सारड़ा का फूलमाला व केशरिया दुपट्टा पहनाकर सम्मान भी किया गया। संयोजक राधेश्याम स्नेहलता मानधन्या ने बताया कि गिरिराज माहेश्वरी मित्र मंडल द्वारा यह फाग महोत्सव, भजन संध्या व सम्मान समारोह का आयोजन पहली बार आयोजित किया गया। 120 सदस्यों वाले इस मंडल में सभी सिनीयर सिटीजन ने फूलों से जमकर होली खेली साथ ही महिलाओं ने राधा-कृष्ण के फाग गीतों का आनंद भी लिया। मुकूट मांगलिक भवन में आयोजित फाग महोत्सव में सुरेश-गीता मंडोवरा गोपालकृष्ण-सुशीला मानधन्या, ओम-शशि सोमानी, जुगलकिशोर राठी, एन.डी-श्यामा माहेश्वरी, बसंतीलाल सोमानी, सतीश राठी, अंजू मानधन्या सहित ग्रुप के सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन दिनेश चितलांग्या ने किया एवं आभार राधेश्याम-स्नेहलता मानधन्या ने माना। वरिष्ठ समाजसेवियों का किया सम्मान -गिरिराज माहेश्वरी मित्र मंडल द्वारा आयोजित फाग महोत्सव के पूर्व वरिष्ठ समाजसेवियों का सम्मान भी इस अवसर पर किया गया। जिसमें रविन्द्र राठी एवं प्रचार मंत्री अजय सारड़ा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। डा रवींद्र राठी ने अपने उद्बोधन में सीनियर सिटीजन को अंपने अनुभव का लाभ अपने बच्चो को देने के लिए प्रेरित किया साथ ही उन्होंने युवा पीढ़ी को समाज की मुख्य धारा से जोडने का आव्हान किया।

पत्नी को पीटने के मामले में पति और ससुराल वालों पर केस दर्ज

इंदौर। पति और ससुराल वालों द्वारा पत्नी को मोगरी से पीटने और ईंट तथा छुरा मारने के दो अलग अलग मामलों में पुलिस ने मारपीट और हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। तेजाजी नगर थाना पुलिस को फरियादिया द्वारकी चौहान निवासी नायता मूडंला ने शिकायत दर्ज करवाते बताया कि उसके पति दिनेश ने अपनी बहन के साथ पूर्व में हुए विवाद को लेकर उसके साथ मोगरी से मारपीट की जिसमें उसने सर तथा पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने फरियादिया की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं अपने मायके में रह रही दूसरी पत्नी के साथ पति ने अपनी पहली पत्नी , मां और बहन के साथ जाकर मारपीट करते उसकी हत्या करने की कोशिश की। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने पूजा परमार उम्र तीस वर्ष निवासी नरवल गांव की रिपोर्ट पर उसके पति जितेंद्र परमार , सास बसंतीबाई परमार , ननद पायल परमार और जितेंद्र की पहली पत्नी गायत्री परमार के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। पूजा ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि कल ये सभी लोग मेरे घर आए। पति ने ईंट और छुरे से वार किए। वहीं सास ननद और गायत्री ने मुझे पकड़ लिया और कहा इसे मार डालो , बचना नहीं चाहिए। इसके बाद वे सभी मुझे छोड़कर भाग गए। पुलिस ने मारपीट और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

सायबर सुरक्षा एवं जागरूकता पर कार्यशाला में डॉ. वरूण कपूर ने कहा

सायबर अपराध से बचाव आपकी जागरूकता पर निर्भर

इंदौर। ब्लैक रिबन पहल, ''संकल्प'' अभियान के तहत डॉ. वरूण कपूर-अति. पुलिस महानिदेशक द्वारा इंडेक्स इंस्टिट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज मालवांचल यूनिवर्सिटी, इंदौर में सायबर सुरक्षा एवं जागरूकता'' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में डेंटल कॉलेज के 113 छात्र-छात्राओं एवं 10 व्याख्याताओं ने भाग लिया।

डॉ. कपूर द्वारा सायबर सुरक्षा एवं जागरूकता के संबंध में सायबर सुरक्षा के लिये साझा प्रयास की आवश्यकता पर बल देते हुये बताया कि वर्तमान में कम्प्यूटर एवं इंटरनेट का उपयोग हमारे जीवन का एक अंग हो गया है। हमारे दैनिक जीवन का काफी समय आभासी दुनिया में व्यतीत हो रहा है। दुनिया के बदलते परिवेश में अपने आप को उसके अनुरूप ढालना होगा क्योंकि यदि आप उससे तालमेल नहीं बैठाते हैं तो किसी खतरे में भी पड़ सकते हैं। वास्तविक दुनिया एवं आभासी दुनिया बड़ा अंतर है।

वास्तविक दुनिया के खतरे दिखाई पड़ते हैं किन्तु आभासी दुनिया के नहीं। वास्तविक दुनिया में उत्पन्न खतरों से पुलिस आपकी सुरक्षा कर सकती है किन्तु सायबर वर्ल्ड में हो रहे सायबर अपराध से बचाव आपकी जागरूकता पर निर्भर है। इसके लिये आपको हमेशा सतर्क एवं जागरूक रहकर सायबर स्पेस का उपयोग करना चाहिए।

सायबर अपराधी अपनी पहचान छुपाकर सोशल मीडिया, ईमेल, चैटरूम इंस्टंट मेसेजिंग, गेमिंग प्लेटफार्म का उपयोग कर शिकार बनाते है और ऐसे कार्य करने के लिये प्रेरित करते हैं जिससे उन्हें आसानी से ब्लैकमेल किया जा सके। सायबर अपराध से बचने के लिये अनजान से संपर्क नहीं करना। यदि वह जाना पहचाना भी हो तो उसकी पड़ताल करें। अंजान फोन,विडियो कॉल, ईमेल,लिंक, एसएमएस को ओपन न करें। व्यक्तिगत जानकारियों को शेयर न करें। व्हाट्सप पर प्रसारित होने वाली अधिकांश जानकारी झूठी होती है। ह्यहमारी छोटी सी चूक भी हमारे लिये मुसीबत का कारण बन सकती है।

अपने बारे में कितनी इंफार्मेशन कब, कैसे और कहॉ शेयर करनी है, शेयर करना भी है या नहीं। इसके लिये सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ सायबर स्पेश का उपयोग करें। इस अपराध को अंजाम देने वाला आपका परिचित, रिश्तेदार, मित्र या कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है।

लोगों द्वारा बिना सोचे-समझे जानकारी पोस्ट फारवर्ड की जाती है। किसी भी संदेश को फारवर्ड करने से पहले उसकी सत्यता की जॉच करें के पश्चात् शेयर या फारवर्ड करें। सायबर अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसकी मुख्य वजह हमारी लापरवाही एवं जानकारी की कमी है। डॉ. कपूर ने छात्र-छात्राओं को सायबर ग्रुमिंग की जानकारी दी गई व इंटरनेट के प्रयोग में अपनायी जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया।

छात्र-छात्राओं के प्रश्नों का समाधान डॉ. कपूर द्वारा सहजता से किया गया। कार्यशाला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दो छात्र-छात्राओं को क्रमशः डॉ. आदिल एवं डॉ. सृष्टि को डॉ. कपूर ने प्रमाण-पत्र व गोल्डन बैज प्रदान कर सम्मानित किया।

भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

सामान्य प्रशासन विभाग की समीक्षा में होगा भ्रष्टों का हिसाब-किताब

भोपाल। *मप्र में अब भ्रष्ट अफसरों की फाइलों से जल्द ही धूल हटेगी। इसकी वजह यह है की भ्रष्टाचार में फंसे अधिकारियों-कर्मचारियों के अभियोजन के मामलों को अब खुद मुख्यमंत्री सचिवालय देखेगा। दरअसल, विगत दिनों मुख्यमंत्री ने भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का संकेत देते हुए ऐसे अफसरों की सूची बनाने का निर्देश दिया था। उसके बाद राज्य सरकार भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों के मामले में सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों से जुड़े प्रकरणों को अगली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सामने रखने की पूरी तैयारी कर ली है। भ्रष्टाचार से जुड़े ये ऐसे प्रकरण हैं, जिनमें जांच एजेंसी लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू ने जांच पूरी कर ली है और अभियोजन स्वीकृति के लिए शासन (संबंधित विभाग) से अनुमति मांगी है। लेकिन अनुमति के इंतजार में इन भ्रष्ट अधिकारियों- कर्मचारियों के प्रकरण न्यायालय में पेश ही नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे सभी प्रकरणों पर मुख्यमंत्री जल्द ही बड़ा निर्णय ले सकते हैं।*

गौरतलब है की प्रदेश में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज है, लेकिन इन अफसरों के खिलाफ पिछले कई सालों से अभियोजन की मंजूरी ही नहीं दी गई है। इससे सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। इसलिए इस मामले को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है और अभियोजन के मामलों को देखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के इस कदम से जहां भ्रष्टाचार के मामले में फंसे अफसरों की चिंताएं बढ़ गई हैं, वहीं लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के अफसरों को उम्मीद है की अब जल्द से जल्द अभियोजन की स्वीकृति मिल जाएगी। बता दें कि कांग्रेस ने सरकार पर अनियमितता के दोषियों को बचाने के लिए अभियोजन की स्वीकृति न देने का आरोप कई बार लगाया है। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसकी समीक्षा की थी, इसके बाद जीएडी ने भ्रष्टों की सूची बनानी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, आबकारी, स्वास्थ्य एवं अन्य विभाग के मामले लंबित है। वरिष्ठ अधिकारी एवं जन प्रतिनिधियों से जुड़े मामले भी लंबित हैं। समीक्षा बैठक में इन पर चर्चा होगी। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसियों के जांच प्रस्ताव के बाद भी विभागों ने अलग से जांच कराई है।

जल्द निर्णय ले सकते हैं सीएम

मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों के मामले में सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों से जुड़े प्रकरणों को अगली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के सामने रखने की पूरी तैयारी कर ली है। भ्रष्टाचार से जुड़े ये ऐसे प्रकरण हैं, जिनमें जांच एजेंसी लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू ने जांच पूरी कर ली है और अभियोजन स्वीकृति के लिए शासन (संबंधित विभाग) से अनुमति मांगी है। लेकिन अनुमति के इंतजार में इन भ्रष्ट अधिकारियों- कर्मचारियों के प्रकरण न्यायालय में पेश ही नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे सभी प्रकरणों पर मुख्यमंत्री जल्द ही बड़ा निर्णय ले सकते हैं। जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न जांच एजेंसियों में दर्ज प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति की निगरानी के लिए काम करना शुरू कर दिया है। इसमें सभी जांच एजेंसियां अभियोजन की स्वीकृति के लिए शासन को भेजे गए प्रकरणों की जानकारी मांगी गई है।अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति भारत सरकार के स्तर पर लंबित होगी तो यह भी पता चल जाएगा। अकेले लोकायुक्त संगठन में लगभग 25 और ईओडब्ल्यू में 10 आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति लंबित है। कई अधिकारी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर स्वीकृति नहीं मिलने देते। यही कारण है कि 10 वर्ष से भी ज्यादा कुछ पुराने मामलों में स्वीकृति नहीं मिली है।

गठित की गई है समिति

भ्रष्टाचार से जुड़े प्रकरणों की पिछली समीक्षा बैठक तत्कालीन शिवराज सरकार के समय विधानसभा चुनाव से पहले हुई थी। तब मुख्यमंत्री ने अभियोजन के मामले तत्काल निपटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन विभागों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री भ्रष्ट अधिकारियों- कर्मचारियों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करने जा रहे हैं। ऐसे मामलों के लिए एक समिति गठित की गई है। जिसमें मुख्यमंत्री समेत मंत्री भी हैं। हालांकि अभी बैठक की तिथि निर्धाधित नहीं हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री कभी भी बैठक बुला सकते हैं। जिसमें भ्रष्ट अधिकारियों- कर्मचारियों को लेकर कड़ा निर्णय लिया जा सकता है। मुख्य तकनीकी परीक्षक पर होगा फैसला- प्रदेश में सभी तरह के निर्माण कार्यों की तकनीकी जांच के लिए गठित संस्था मुख्य तकनीकी परीक्षक (सीटीए) सतर्कता को लेकर भी फैसला होना है। क्योंकि बुंदेलखंड पैकेज घोटाले की जांच के बाद सीटीए का मप्र में अस्तित्व खत्म सा हो गया है। लंबे समय से सीटीए की नियुक्ति नहीं हो पाई है। सरकार ने सीटीए पर ध्यान ही देना बंद कर दिया है। हालांकि सीटीए को बंद करने या फिर से ताकतवर बनाने पर भी फैसला होना है।

राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे 'पीड़ित'

किसानों, बेरोजगारों, युवाओं, कर्मचारियों को साधेगी कांग्रेस

भोपाल। *राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मध्यप्रदेश में प्रभावी बनाने के लिए कांग्रेस 'पीड़ितों' को साधेगी। यात्रा के मद्देनजर कांग्रेस के वरिष्ठों की मंत्रणा में नए प्लान को अमलीजामा पहनाया गया। जल्द ही किसानों, बेरोजगारों, व्यापमं गड़बड़ी मामले के साथ पटवारी परीक्षा से जुड़े युवाओं, ओपीएस समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन की राह पकड़े कर्मचारी संगठनों से संपर्क करेगी। ताकि न्याय यात्रा से इन्हें जोड़ा जा सके।*

कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने बताया कि आगामी दो मार्च को राजस्थान के धौलपुर से होते हुए राहुल गांधी की यात्रा मुरैना में प्रवेश करेगी। तैयारियों के साथ मुद्दों के रोडमैप को पहले ही तैयार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि

बीजेपी सरकार से तमाम त्रस्त वर्गों से संपर्क किया जाएगा जिन्हें वोटों की राजनीति के लिए मोहरा बनाया गया। केंद्र से लेकर राज्य सरकार की तमाम अधूरी घोषणाओं पर भी बात होगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रदेश के सभी शोषित वर्गों राहुल गांधी की यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे।

कांग्रेस का इन पर फोकस-कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है उसके अनुसार, यात्रा के मद्देनजर धान और गेहूं खरीदी को लेकर किसानों से संपर्क किया जाएगा। आदिवासियों पर अत्याचार, एफआईआर और अन्य मुद्दों को लेकर जनजाति वर्ग से संपर्क किया जाएगा। वहीं लाडली बहना योजना में तीन हजार रुपये प्रति माह की घोषणा को लेकर महिलाओं से, व्यापमं, पटवारी, कृषि विस्तार समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के मामलों को लेकर बेरोजगारों और सरकारी कर्मचारी संगठनों से उनकी मांग समेत ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली को लेकर संपर्क किया जाएगा। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि इन वर्गों को यात्रा से जोडने के लिए अलग-अलग नेताओं को जिम्मेदारी भी लगभग तय की गई है। इसमें आदिवासी नेताओं से संपर्क के लिए विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, विधायक विक्रांत भूरिया, किसानों से पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत, युवाओं से संपर्क हेमंत कटारे, कुणाल चौधरी समेत अन्य नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। कर्मचारी संगठनों के लिए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, महेंद्र चौहान, सुरेश पचौरी संवाद करेंगे। इसके अलावा अलग-अलग प्रकोष्ठों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सील की गई पटाखा दुकानों के लाइसेंस होंगे निरस्त

भोपाल। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद शहर में पटाखा दुकानों और गैस एजेंसियों को लेकर जिला कलेक्टर द्वारा सख्ती बरती जा रही है। पिछले दिनों कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए थे कि पटाखा दुकानों और गैस एजेंसियों की जांच कर रिपोर्ट तैयार करें। इसी के आधार पर सभी एसडीएम को सील की गई पटाखा दुकानों के लाइसेंस अब निरस्त करने और रहवासी क्षेत्र से इन्हें बाहर शिफ्ट करने की कार्रवाई करनी होगी। इसके साथ ही आबादी वाले क्षेत्र में चल रही गैस एजेंसियों के गोदाम भी बाहर करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर संत हिरदाराम नगर के तत्कालीन एसडीएम आदित्य जैन ने एक सप्ताह पूर्व जांच कर रिपोर्ट सौंपी थी। जिसमें बताया गया था कि हलालपुर लालघाटी स्थित पटाखा बाजार में आतिशबाजी की 15 दुकानें हैं। इसके साथ ही बाजार के बाहर भी आसपास पटाखा दुकानें संचालित हो रही हैं। इनके पास ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कालोनियां, पेट्रोल पंप, मैरिज गार्डन आदि स्थित हैं। ऐसे में इनको बाहर करना ही उचित रहेगा। इसी तरह हुजूर एसडीएम आशुतोष शर्मा और बैरसिया के तत्कालीन एसडीएम विनोद सोनकिया ने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वहीं, एमपी नगर एसडीएम एलके खरे ने खजूरी कलां की गैस एजेंसी गोदाम को बाहर करने का प्रस्ताव कलेक्टर को सौंपा था।

विस्फोटक शिफ्ट करें या नष्ट-कलेक्टर ने विस्फोटक निर्माताओं, भंडारणकर्ताओं एवं विक्रेताओं की जांच रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि अभियान के तहत सील की गई दुकानों के लाइसेंस रद किए जाएं। भंडारण किए हुए विस्फोटक को शिफ्ट किया जाए या नष्ट करने की कार्रवाई की जाए। कोई भी भंडारण आबादी वाले स्थानों पर न हो, इसके साथ ही खाद्य आपूर्ति विभाग को निर्देश दिए कि जिले में गैस एजेंसी भंडारण केंद्रों को आबादी क्षेत्रों से बाहर शिफ्ट किया जाए। सभी गैस एजेंसियों को जारी एनओसी की समीक्षा की जाए।

लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कार्यालय में बैठक संपन्न

बूथ पर 370 अधिक मत का लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले 100 दिन शत प्रतिशत समर्पण भाव से जुटें

भोपाल। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें जिताने के लिए प्रधानमंत्री जी के हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का आव्हान, धारा 370 की समाप्ति के लिए डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बलिदान को नमन है। हमें इस 370 के आंकड़े से जुड़े भावनात्मक संदेश को प्रत्येक बूथ तक पहुंचाना है और हर कार्यकर्ता को इससे जोड़ना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगामी 100 दिनों की कार्ययोजना तैयार करें और परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ उसे जमीन पर उतारने में जुट जाएं। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा, लोकसभा प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने गुरुवार को आयोजित प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजकों की बैठक को संबोधित करते हुए कही।

प्रदेश का वातावरण सकारात्मक, मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए काम करें: डॉ. मोहन यादव-बैठक में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस चुनाव से हमारे विजय अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व एवं डबल इंजन सरकार के कार्यों से प्रदेश का वातावरण हमारे पक्ष में है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता उपलब्ध समय का उपयोग मत प्रतिशत बढ़ाने में करें। उन्होंने आगामी कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए कहा कि आगामी समय में प्रधानमंत्री जी 'विकसित मध्यप्रदेश' कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। प्रदेश के 163 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे विधायक हैं, और जहां विधायक नहीं हैं, वहां क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि कार्यक्रम का गरिमापूर्ण आयोजन सुनिश्चित करें। 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्यप्रदेश के प्रवास पर आ रहे हैं। इसके अलावा मन की बात कार्यक्रम भी है। डॉ. यादव ने कहा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि यह कार्यक्रम नमो एप और संगठन एप पर अधिक से अधिक अपलोड हो। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि पार्टी के प्रचार-प्रसार के लिए दीवार लेखन जैसे जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनमें सभी की सक्रियता से सहभागिता हो। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्यप्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में विकास के नए आयाम गढ़े गए हैं। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारत विकास के हर क्षेत्र में और लंबी छलांग लगाएगा। इस बार प्रदेश की जनता सभी 29 की 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा को भरपूर आशीर्वाद देगी। सभी सीटें हम जीतकर इतिहास दर्ज करेंगे।

नेतृत्व पर जनता का विश्वास, सरकार की योजनाएं, संगठन तंत्र हमारी ताकतः विष्णुदत्त शर्मा

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि 2023 के चुनाव में हमें जो प्रचंड जीत मिली है, उसका श्रेय हमारी टीम और कार्यकर्ताओं को जाता है। प्रधानमंत्री ने भी इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की टीम भावना को दिया है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में माहौल पार्टी के पक्ष में है और कार्यकर्ता आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। सभी मोर्चों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। जो परिश्रम हमने विधानसभा चुनाव के समय किया था, उससे अधिक परिश्रम लोकसभा चुनाव से पहले करना है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है-लोकसभा चुनाव बूथों पर लड़ा जाएगा, हमें हर आने वाले कार्यक्रम को बूथ स्तर तक ले जाना है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने झाबुआ की सभा में हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने की जो जड़ी-बूटी दी थी, उसे हमें हर बूथ तक ले जाना है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में जो काम हुए हैं, उनसे लोगों का जीवन बदला है। दूसरी तरफ कांग्रेस जैसे दल आज भी भगवान श्रीराम का अपमान कर रहे हैं। ऐसे में अन्य दलों के लोग और आमजन पार्टी से जुड़ने के लिए तत्पर हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की इस प्रेरणा का लाभ लेते हुए हमें अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में शामिल करना है। श्री शर्मा ने कहा कि हमारे नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास, हमारी सरकारों की योजनाएं तथा हमारा संगठन तंत्र हमारी ताकत है। इन्हीं को लेकर सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से जमीन पर उतरेंगे और प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतेंगे तथा पार्टी के वोट शेयर को भी बढ़ाएंगे।

आईपीएस अफसरों ने जमीनों में जमकर किया निवेश, 23 अफसरों ने नहीं दी अपनी संपत्ति की जानकारी

भोपाल। प्रशासन की बागडोर संभालने वाले मप्र के कुछ आईपीएस अफसर किसी धन्नासेठ से कम नहीं हैं। उनकी संपत्ति दिन-रात बढ़ रही है। इसका खुलासा मप्र कैडर के आईपीएस अधिकारियों द्वारा पेश किए गए संपत्ति के ब्यौरे से हुआ है। खास बात है कि मध्य प्रदेश के 246 अफसर ने ही संपत्ति की जानकारी दी है, जबकि 23 आईपीएस में कोई भी रिकॉर्ड संपत्ति के बारे में नहीं जमा किया है। जानकारों का कहना है कि अफसरों द्वारा संपत्ति बताने में पर्देदारी की जा रही है। प्रदेश के आईपीएस अफसर अपनी पूरी संपत्ति नहीं बता रहे हैं। हाल ये है कि अफसर सिर्फ जमीन-बंगले बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। यहां के अधिकारी संपत्ति की जानकारी देने में काफी हिचकिचाते हैं, जबकि बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है।

झारखंड सहित कई राज्यों में आइएएस अफसर जेवर, गिफ्ट सहित अन्य सामानों तक की जानकारी दे देते हैं जबकि मध्यप्रदेश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सिर्फ जमीन और मकान की जानकारी ही देते हैं। यही कारण है कि 2024 की प्रॉपटी डिटेल में अफसरों का जमीन से मोह साफ दिखता है। ब्यौरे के मुताबिक मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी शैलेश सिंह के पास सबसे ज्यादा पुश्तैनी जमीन है, वहीं ईओडब्ल्यू में पदस्थ डीजी अजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें हर महीने ढाई लाख रूपये की आय किराए से होती है। इसमें दिल्ली के फ्लैट से 2 लाख से अधिक किराया मिलता है।

भोपाल के एक मकान से 66 हजार से अधिक किराया मिलता है, हाउसिंग सोसाइटी में बने प्लॉट से 1 लाख 10 हजार की आय होती है। साथ ही चंदनपुर परिवार की जमीन से डेढ़ लाख रुपए का रेंट उन्हें हर महीने मिलता है। स्पेशल डीजी गोविंद प्रताप ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास मध्य प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश में कई जमीनें हैं इसके अलावा उनके पास कई संपत्तियां ऐसी है जिसे उन्होंने जमीन बेचकर खरीदा है।

स्वास्थ्य विभाग में 3 हजार 323 पदों में होगी नियुक्ति

उम्मीदवारों को न हो असुविधा- उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

***भोपाल।** उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने निर्देश दिए हैं कि कि स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के परीक्षण एवं मेडिकल जांच में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सभी संबंधित अधिकारी संवेदनशीलता से कर्तव्यों का निर्वहन करें।*

उल्लेखनीय है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 12 फरवरी को घोषित परिणाम के अनुक्रम में स्वास्थ्य विभाग में 3 हज़ार 323 पदों पर नियुक्ति की जा रही है। इनमें ए.एन.एम. के 2 हज़ार 576, रेडियोग्राफर तृतीय श्रेणी के 104, प्रयोगशाला तकनीशियन के 228, फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के 415 पद शामिल हैं।

29 फरवरी को पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सिंगल क्लिक के माध्यम से-प्रयोगशाला तकनीशियन तथा रेडियोग्राफर के नियुक्ति आदेश संभागीय क्षेत्रीय संचालक द्वारा तथा ए.एन.एम. व फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के नियुक्ति आदेश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किया जाना है। भोपाल में 29 फरवरी को आयोजित समारोह में पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे। इसके लिये चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण तथा मेडिकल करवाया जाना आवश्यक होगा।

सभी जिला चिकित्सालय और संभागीय मुख्यालय में लगाये जाएँगे विशेष शिविर

आयुक्त स्वास्थ्य डॉ सुदाम खाड़े ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों के मेडिकल तथा दस्तावेजों का परीक्षण के लिए जिला अस्पतालों में प्रातः 9 से शाम 5 बजे तक विशेष शिविर लगाये जायेंगे। ए.एन.एम. उम्मीदवारों का जिला चिकित्सालयों में 22 से 26 फरवरी, फार्मासिस्ट ग्रेड-2 का जिला चिकित्सालयों में 23 से 25 फरवरी, रेडियोग्राफर उम्मीदवारों का संभागीय मुख्यालय के जिला चिकित्सालय में 24 फरवरी को और प्रयोगशाला तकनीशियन का संभागीय मुख्यालय के जिला चिकित्सालय में 25 फरवरी को मेडिकल जाँच और दस्तावेजों का परीक्षण किया जाएगा। जिला चिकित्सालयों में मेडिकल जांच की जिम्मेदारी सभी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की होगी। क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दस्तावेजों की जांच के लिए समुचित अमले की व्यवस्था करेंगे।

भोपाल मास्टर प्लॉन का नया ड्रॉफ्ट 2047 की आबादी को ध्यान में रखकर तैयार होगा

नगरीय विकास मंत्री श्री विजयवर्गीय ने जन-प्रतिनिधियों से आमंत्रित किये सुझाव

भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि राजधानी भोपाल का मास्टर प्लॉन जन-प्रतिनिधियों के दिये गये सुझाव के आधार पर तैयार किया जायेगा। यह मास्टर प्लॉन वर्ष 2047 की आबादी को ध्यान में रखकर तैयार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राजधानी का सुव्यवस्थित विकास हो और नागरिकों को सभी बुनियादी सुविधाएँ सुलभ तरीके से मिल सके, इसके लिये सभी आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे।

नगरीय विकास मंत्री श्री विजयवर्गीय आज मंत्रालय में भोपाल मास्टर प्लॉन के ड्रॉफ्ट के संबंध में बुलाई गई बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर, भोपाल महापौर मालती राय, सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, विधायक रामेश्वर शर्मा, श्री आतिफ अकील, पूर्व विधायक श्री ध्रुव नारायण सिंह, पूर्व निगम अध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा और प्रमुख सचिव नीरज मण्डलोई भी मौजूद थे। नगरीय विकास मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि भोपाल के तालाब विशेष रूप से बड़ा तालाब राजधानी की लाइफ लाइन माना जाता है और भोपाल आने वाले पर्यटकों के लिये विशेष आकर्षण का केन्द्र रहता है। तालाब और भोपाल की पुरातत्वीय विरासत को संरक्षित करते हुए मास्टर प्लॉन में प्रावधान किये जायेंगे। उन्होंने जन-प्रतिनिधियों से कहा कि राजधानी भोपाल का पृथक से ट्रेफिक प्लॉन तैयार किया जायेगा। इसमें सड़कों की पर्याप्त चौड़ाई, फ्लॉय-ओवर और मेट्रो सेवा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

अनुष्का शर्मा से पहले इन एक्ट्रेस ने छिपाई प्रेग्नेंसी

लंबे समय तक प्रेग्नेंसी की न्यूज छिपाने के बाद अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने बेबी बॉय के जन्म की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर कर दी है। लेकिन अनुष्का ही अकेली एक्ट्रेस नहीं हैं, जिन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी की न्यूज छिपाई. आइए, यहां जानते हैं कौन-कौन सी एक्ट्रेस अपनी प्रेग्नेंसी की न्यूज छिपा चुकी हैं।

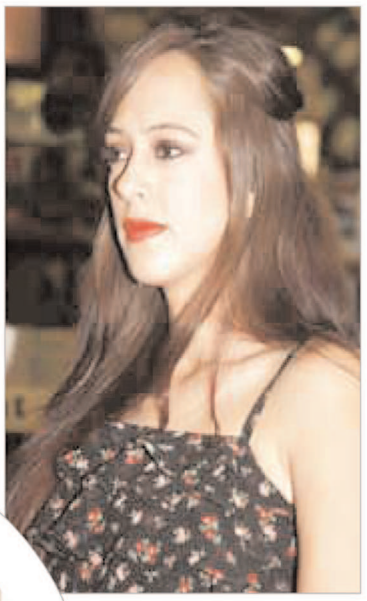

अनुष्का शर्मा

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली 15 फरवरी को अपने दूसरे बच्चे के पैरेंट्स बने हैं। एक्ट्रेस अनुष्का ने अपनी प्रेग्नेंसी की खबर पूरे पीरियड में ऑफिशियल नहीं की थी। और सीधा ही बेबी बॉर्न की न्यूज फैंस संग शेयर की।

रुबीना दिलैक- एक्ट्रेस रुबीना दिलैक ने भी अपनी प्रेग्नेंसी की न्यूज लंबे समय तक फैंस से छिपाकर रखी थी। रुबीना दिलैक ने अपनी ट्विन्स बेबी के जन्म की खबर भी फैंस के साथ करीब एक महीने बाद जाकर शेयर की थी।

हेजल कीच

क्रिकेटर युवराज सिंह की पत्नी और एक्ट्रेस हेजल कीच ने भी अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की न्यूज ऑफिशियल नहीं की थीं। हेजल और युवराज ने बेबी होने के बाद फैंस के साथ गुडन्यूज शेयर की थी। बता दें, हेजल कीच ने बीते साल अगस्त के महीने में बेटी को जन्म दिया था।

दीपिका कक्कड.- एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने भी लंबे समय तक अपनी प्रेग्नेंसी को छिपाकर रखा था। प्रेग्नेंसी के काफी समय बाद दीपिका कक्कड़ और उनके पति ने फैंस के साथ गुडन्यूज शेयर की थी।

इलियाना डिक्रूज- एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज ने भी लंबे समय तक प्रेग्नेंसी की न्यूज छिपाकर रखी थी. लेकिन जैसे ही एक्ट्रेस ने गुडन्यूज अनाउंस की, वैसे ही सोशल मीडिया पर हाय-तौबा मच गया था. क्योंकि इलियाना ने अपने रिलेशनशिप या शादी के बारे में किसी कोई अपडेट नहीं दिया था। इलियाना ने अभी तक भी अपने मैरिटल स्टेटस पर कोई खुलासा नहीं किया है।

पलक तिवारी को लोगों ने बुरी तरह किया ट्रोल

श्वेता तिवारी अपनी खूबसूरती और फिटनेस के लिए फैंस के बीच मशहूर हैं। अकसर उनकी बेटी पलक को लोग उनकी बहन भी समझ बैठते हैं। समझें भी कैसे ना, श्वेता हैं ही इतनी खूबसूरत। एक्ट्रेस की बेटी पलक की भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। इन दिनों पलक एक बार फिर चर्चा में आई हैं। मगर इस बार वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल, पलक तिवारी अपनी मां की ही तरह अकसर फैंस के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। हर बार फैंस से उन्हें खूब तारीफ भी मिलती है। मगर इस बार पलक ने कुछ ऐसा कर दिया कि उन्हें तारीफ की जगह ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। असल में ट्रोलिंग के साथ साथ फैंस पलक से बेहद नाराज भी दिखे।

दरअसल, हाल ही में पलक तिवारी ने एथनिक वीयर में एक शूट कराया। पलक इसमें बेहद खूबसूरत लग रही थीं। पलक ने सूट पहना हुआ था और मिनिमल मेकअप किया हुआ था। ये तस्वीरें फैजा सकलेन ने शेयर की थीं, जो मशहूर पाकिस्तानी डिजाइनर हैं। मगर देखते ही देखते पलक की इन तस्वीरों पर यूजर्स का गुस्सा जमकर फूट पड़ा। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी लोग उन्हें बुरा भला कहने लगे। दरअसल, फैंस पाकिस्तानी डिजाइन पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि उन्होंने शूट के लिए पलक को ही क्यों चुना। पाकिस्तान में तो एक से बढ़कर एक हसीनाएं हैं।

जोड़ों के दर्द को न लें हल्के में, हो सकते हैं गंभीर बीमारी के शिकार

हैल्थ विशेषज्ञों के मुताबिक

भारत में हर साल गठिया के 1 करोड़ से ज्यादा केस सामने आते हैं। हालांकि, घुटने खराब करने में मोटापा, इंजरी, शुगर जैसी कई बीमारियों का भी रोल है। लेकिन सबसे बड़ी वजह है आर्थराइटिस। ऐसे में इस बीमारी से बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है।

आर्थराइटिस में ऐसे करें परहेज

अगर आप आर्थराइटिस की समस्या से परेशान हैं तो सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान दें और इन कुछ फूड्स से तुरंत दूरी बनायें। जैसे- ठंडी चीज़ें ना खाएं, चाय-कॉफ़ी ना लें, टमाटर ना खाएं, शुगर कम करें, ऑयली खाने से बचें, वजन कंट्रोल रखें, प्रोसेस्ड फूड खाने से बचें, ग्लूटेन फूड का सेवन न करें, अल्कोहल का सेवन न करें साथ ही ज्यादा चीनी और नमक भी कम से कम खाएं।

पहले तो उम्र के साथ घुटने कमजोर होते थे, लेकिन अब तो यंगस्टर्स भी ज्वाइंट्स पेन की परेशानी झेल रहे हैं। हमारे देश में जोड़ों के दर्द से परेशानी इतनी कॉमन हो गई है कि देश में 15 करोड़ से ज्यादा घुटनों के मरीज हैं। हेल्थ विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में हर साल गठिया के 1 करोड़ से ज्यादा केस सामने आते हैं। हालांकि, घुटने खराब करने में मोटापा, इंजरी, शुगर जैसी कई बीमारियों का भी रोल है। लेकिन सबसे बड़ी वजह है आर्थराइटिस। ऐस में इस बीमारी से बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। दरअसल, जब जोड़ों के बीच का तेल खत्म हो जाता है और हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं तो नसें खुल जाती हैं। इस वजह से घुटनों में तेज दर्द शुरू हो जाता है और शुरू होती है आर्थराइटिस की समस्या। क्योंकि लोगों का लाइफ स्टाइल बिगड़ा हुआ है। गलत पॉश्चर में बैठने, उल्टा सीधा खाने, योग-वर्कआउट ना करने और पॉल्यूशन से लोगों की हड्डियां कमजोर हो रही हैं।

आर्थराइटिस और लक्षण

पैर के अंगूठे में सूजन एवं दर्द
-घुटनों में सूजन और उसका चटकना
-शरीर के अन्य जोड़ों में तेज दर्द
-मरीज को दर्द के साथ बुखार आना
-चलने-फिरने में जोड़ों में तकलीफ होना

हड्डियां मजबूत बनाने के लिए करें इन चीजों का सेवन

अर्थराइटिस से बचने के लिए अपने खाने में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाएं, रोजाना 1 कप दूध जरूर पीएं, लौकी के जूस को अपनी डाइट में शमिल करें। साथ ही सेब का सिरका भी पीएं, गुनगुने पानी में दालचीनी-शहद पीने से आपकी कमजोर हड्डियां मजबूत होंगी। इसके साथ ही बादाम, अखरोट, पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें।

इन बातों का भी रखें ध्यान

यूरिक एसिड बढ़ने पर अर्थराइटिस की समस्या बढ़ जताई है। इसलिए यूरिक एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन न करें। खाना बनाने के लिए ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। यह शरीर के लिए फ़ायदेमदं है तथा इसमें विटामिन-ई की भरपूर मात्रा होती है जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करता है। अपने वजन को बढ़ने न दें। वजन बढ़ने से भी इसकी परेशानी बढ़ जाती है। कम से कम स्मोकिंग करें। नियमित रूप से योग करें। साथ ही अपना पॉश्चर सही रखें।

इन एक्टिविटी से बच्चों की बढ़ा सकते हैं ग्रोथ

पढ़ाई-लिखाई के अलावा छोटे बच्चों को कुछ खास एक्टिविटी करवाते रहना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए कुछ खास करना चाहती हैं तो हम आपको बताएंगे कि आप उन्हें कौन-कौन सी एक्टिविटी करवा सकती हैं। इससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास काफी अच्छा होगा।

एक्टिंग सिखाएं

अगर उन्हें एक्टिंग का शोक है तो आपको बचपन से ही उन्हें एक्टिंग सीखना चाहिए। ऐसे में आपके बच्चे बड़े होकर इस छेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। बच्चों को हमेशा उनकी रुचि के हिसाब से ही एक्टिविटी करवाना चाहिए।

कराटे सिखाएं

बच्चों को खुद की सुरक्षा करना आना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहती हैं तो आपको अपने बच्चों को कराटे जरूर सीखाना चाहिए। खासकर लड़कों को कराटे करने का काफी शौक होता है। ऐसे में आपको उन्हें कराटे की क्लास के लिए भेजना चाहिए।

पेंटिंग क्लास

आप अपने छोटे बच्चों को पेंटिंग की क्लास के लिए भी भेज सकती हैं। लड़कियों को पेंटिंग करने का शोक होता है। अगर वह बचपन से ही इन चीजों की क्लास करती हैं तो वह बड़े होकर अपना करियर भी इस फिल्ड में बना सकती हैं। इसलिए अगर आपके बच्चों को पेंटिंग करना पसंद है तो उन्हें क्लास के लिए जरूर भेजे।

स्केटिंग क्लास

स्केटिंग क्लास आप अपने बच्चों को करवा सकती है। छोटे बच्चे किसी भी चीज को आसानी से सीख लेते हैं। ऐसे में उन्हें आदत हो जाती है। ऐसे में आपको अपने बच्चों को स्केटिंग क्लास के लिए जरूर भेजना चाहिए।

सराफा चौपाटी शिफ्ट करने की सिफारिश

इंदौर। इंदौर में जायका के लिए मशहूर रात में लगने वाली सराफा चौपाटी को शिफ्ट करने की सिफारिश कर दी गई है। नगर निगम द्वारा गठित कमेटी ने इस आशय की रिपोर्ट बना ली है। इसे कभी भी महापौर पुष्यमित्र भार्गव को सौंपा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, आज ही इसे सौंपा जाएगा। मुख्य रूप से इसमें जो सिफारिश की गई हैं, उसमें कहा है कि सराफा चौपाटी खतरनाक स्थिति में है। यहां पाइप लाइन से गैस सप्लाय को भी कमेटी ने अव्यवहारिक बताया है। इधर, महापौर भार्गव ने कहा कि अभी कमेटी की जांच रिपोर्ट नहीं मिली है। कमेटी ने जो भी सिफारिश की है, उस पर पहले जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से चर्चा की जाएगी। शहरहित में जो भी निर्णय होगा, लिया जाएगा।

हरदा में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद सराफा चौपाटी पर रातभर जलने वाले सिलेंडर और संकरी गलियों में सोने की कारीगरी भी सिलेंडर पर होने का मुद्दा उठा था। सराफा के व्यापारियों ने यहां बड़े हादसे का डर जताया था। इसके बाद नगर निगम ने कमेटी बनाई थी, जिसने 16 फरवरी की रात सराफा चौपाटी का निरीक्षण किया था। इसमें गलियां, मकान, पार्किंग, ट्रैफिक, गैस सिलेंडर, बिजली कनेक्शन, भीड़ आदि की स्थिति देखी थी।

कमेटी ने मुख्य सराफा बाजार, चौपाटी और रहवासियों से बात की थी। इनमें से अधिकांश ने चौपाटी को कहीं और शिफ्ट करने का सुझाव सामने आया है। इसकी वजह यहां सैकड़ों की तादाद में गैस सिलेंडरों के कारण खतरा बताया जा रहा है।

दूसरी ओर मुख्य सराफा बाजार ही नहीं, आसपास के 13 बाजारों के व्यापारी भी अब इसे हटाने के समर्थन में आ गए थे। उनका कहना है कि चौपाटी का दायरा धान गली, शक्कर बाजार, पिपली बाजार, खजूरी बाजार तक बढ़ने लगा है। यहां भी ऐसी ही समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। सभी पक्षों से बात करने के बाद जांच में कमेटी के अधिकतर सदस्यों ने भी इसे खतरा मानते हुए दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की सिफारिश की है। मंगलवार शाम को कमेटी के सभी सदस्य महापौर को रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद इसे कोर कमेटी में रखा जाएगा। अंतिम दौर में महापौर सहित सभी जनप्रतिनिधियों की राय ली जाएगी।

बीआरटीएस पर एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए मिट्टी परीक्षण का काम शुरू

इंदौर। सबसे व्यस्त मार्ग बीआरटीएस पर छह किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का जमीनी काम शुरू हो गया है। इसके लिए एलआईजी से पलासिया तिराहे तक लोक निर्माण विभाग ने मिट्टी परीक्षण किया है। विभाग ने दो साल में कॉरिडोर के निर्माण का लक्ष्य रखा है। निर्माण के दौरान बीआरटीएस के अलग-अलग हिस्सों का ट्रैफिक भी डायवर्ट होगा।

एलआईजी चौराहा से नवलखा तक बन रहे इस कॉरिडोर की चौड़ाई 15.5 मीटर होगी। इस कॉरिडोर की तीन भुजाएं भी होगा। पहली भुजा ग्रेटर कैलाश मार्ग की तरफ होगी, जबकि दूसरी भुजा गीता भवन चौराहे पर मधुमिलन चौराहे की तरह बनेगी। तीसरी भुजा व्याइट चर्च चौराहा पर पिपलियाहाना की तरफ रहेगी। इस ब्रिज पर फुटपाथ नहीं होंगे। लोक निर्माण विभाग के अफसरों का कहना है कि मिट्टी परीक्षण के बाद खुदाई का काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 17 जनवरी को बीआरटीएस एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमिपूजन किया था। इसके निर्माण पर साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये की लागत आएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दो साल पहले इस प्रोजेक्ट की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। उनसे पहले केंद्र में मंत्री रहने के दौरान कमल नाथ ने भी इंदौर के लिए यह प्रोजेक्ट मंजूर किया था, लेकिन तब राज्य सरकार ने कॉरिडोर बनने से इनकार कर दिया था। अभी बीआरटीएस पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है। कॉरिडोर बनने के बाद 46 प्रतिशत ट्रैफिक उस पर शिफ्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा सुविधा एलआईजी से सीधे नवलखा व भंवरकुआं की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को होगी। एलआईजी से पलासिया तिराहा की तरफ जाने वाला ट्रैफिक भी कॉरिडोर पर शिफ्ट होगा, क्योंकि तिराहे पर उतरने के लिए एक भुजा भी रहेगी। बीआरटीएस का यह हिस्सा बॉटलनेक है और सबसे ज्यादा ट्रैफिक में परेशानी भी यहां आती है।

धोखाधड़ी मे शासकीय अधिकारियों व उनके साथी पर धोखाधड़ी का केस

इंदौर। इंदौर के बिल्डर जसपाल गौड के साथ सड़यंत्र करते हुए मोहन वास्कले अति.जिला पंचायत सीईओ ने पहले तो धोखाधड़ी करते हुए बिल्डर से अपना मकान बनवा लिया और फिर झूठा आश्वासन देकर अपने साडू नानूराम वास्कले आबकारी अधिकारी का बंगला भी सिलिकॉन सिटी में बनवा लिया और बिल्डर की राशि का भुगतान ना करते हुए विगत 4 वर्षो से बिल्डर और उसके परिवार को अत्यधिक प्रताड़ित किया शासकीय अधिकारियों के संरक्षण में उनके साथीगण धर्मेंद्र दिवाकर और प्रशांत सेंगर ने भी बिल्डर के साथ धोखाधड़ी कर दी। बिल्डर की पत्नी किरण ने बताया मोहन ने सितम्बर 2023 में मेरे पति को पैसे देने का बोल कर अपने ऑफिस खंडवा बुलाया और वहां से मेरे पति जसपाल को गायब कर दिया जिसकी रिपोर्ट हमने थाने पर की 6 माह बाद जांच उपरांत अन्नपूर्णा पुलिस ने आरोपीगण के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया। मेरे पति के साथ आरोपीगण ने कोई अनहोनी घटना कारीत कर दी उनका 6 माह से कोई पता नहीं चल रहा है।

तीसरी बार भी कार्यकाल बढ़ाने में लगे निगम कमिश्नर के पीए शर्मा

कई मामलों में निगम आयुक्त तक भी हैं नाराज शर्मा से

इंदौर। दो बार संविदा नियुक्ति लेकर अपना कार्यकाल बढ़ावा चुके निगम कमिश्नर के पीए कृष्ण मुरारी शर्मा एक बार फिर कार्यकाल बढ़ाने के लिए कोशिश में लगे हैं। शर्मा विभागीय मंत्री से लेकर अन्य सभी वरिष्ठों के यहां से कोशिश कर तीसरी बार भी कार्यकाल बढ़ाना चाह रहे हैं। जहां तक शर्मा की कार्यशैली का सवाल है उनके लंच टाइम के बाद करीब 3 बजे आफिस आने से स्वयं निगम कमिश्नर भी नाराज हैं। इसे लेकर कमिश्नर शर्मा को कई बार चेतावनी भी दे चुकी हैं। अन्य कुछ और भी ऐसे मामले हैं जिन्हें लेकर कई बार निगम कमिश्नर ने पीए कृष्ण मुरारी शर्मा को फटकार तक लगाई है।

जानकारी अनुसार निगम आयुक्त कार्यालय में निज सहायक का कार्य देख रहे शर्मा उम्र के 62 से ज्यादा बसंत पार कर चुके हैं। सूत्रों की मानें तो शर्मा की कार्यशैली से भी निगम का हर कर्मचारी ही नहीं, वहां आने वाले लोग तक भी भली-भांति परिचित हैं। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि पीए शर्मा का काम तीन लोगों की एक टीम निगम आयुक्त कार्यालय में करती है। इनमें दो अन्य कर्मचारी सारे मामले बारीकी से देखते हैं। उसका पूरा अध्ययन करने के बाद शर्मा को पूरी जानकारी देते हैं। फिर मामले में आगामी कार्रवाई शुरू होती है। कई बार फटकार फिर भी लेट ही आते हैं ऑफिस–शर्मा के ऑफिस लेट आने को लेकर निगम कमिश्नर ने कई बार फटकार तक लगाई है लेकिन उसके बाद भी शर्मा के ऑफिस लेट आने की आदत में कोई सुधार नहीं हुआ है। खैर अब देखते हैं कि कई तरह की नाराजगी और ऑफिस लेट आने की आदत के बाद भी शर्मा का तीसरी बार कार्यकाल बढ़ता है या उन्हें घर भेजा जाता है।

बिना मान्यता स्कूल मिला तो डीईओ के खिलाफ होगी कार्रवाई

इंदौर। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों की मॉनिटरिंग प्रारंभ की है। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों से स्कूलों की मान्यता से लेकर तीन सत्रों की रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं बिना मान्यता के प्रवेश देने वाले स्कूल को बंद कर दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नया शिक्षा सत्र शुरू होने के पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों की मान्यता को लेकर कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत जिन स्कूलों की मान्यता 2023-24 को समाप्त हो रही है, उन स्कूलों द्वारा 2024- 25 में मान्यता नवीनीकरण कर दिया गया है। इसका प्रमाण संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, संभागीय संयुक्त संचालकों को लोक शिक्षण संचालनालय को देना होगा। यह जानकारी भी देना होगी कि उनके जिले में अब कोई भी स्कूल 2024-25 से मान्यता नवीनीकरण करने के लिए शेष नहीं है। स्कूलों की मान्यता के संबंध में लोक शिक्षण आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने सभी डीईओ को निर्देश दिए हैं कि वे यह रिपोर्ट भी दें कि उनके जिले में ऐसा कोई स्कूल नहीं है, जिसकी मान्यता 2021-22 और 2022 23 में समाप्त हो चुकी है। उनके द्वारा पिछले वर्ष यानी 2023-24 के लिए आवेदन नहीं किया गया था।

स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयार किया नया फार्मूला

5वीं-8वीं के हर जिले में अलग-अलग बनाए जाएंगे पेपर

इंदौर। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बार पेपर लीक से निपटने के लिए नया फामूर्ला तैयार किया है। विभाग ने इस बार हर जिले के लिए अलग-अलग प्रश्नपत्र तैयार किया है, ताकि किसी एक जिले में पेपर लीक होने पर सिर्फ उसी जिले की परीक्षा को निरस्त किया जा सके। यह व्यवस्था इस बार पांचवीं-आठवीं बोर्ड परीक्षा में की गई है।

बोर्ड परीक्षा के लिए सख्ती बरती गई है कि अगर फामूर्ला सफल रहा तो आगे 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा में भी अपनाया जाएगा। इस बार पांचवीं व आठवीं की बोर्ड परीक्षा के लिए विभाग की ओर से काफी सख्ती बरती गई है। वहीं, प्रदेश के 15 फीसद केंद्रों पर उसी दिन प्रश्नपत्रों को फोटो कापी कर विद्यार्थियों में वितरित किया जाएगा। सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों का परीक्षा केंद्र भी उसी स्कूल में न होकर पांच से 10 किमी दूर कर दिया गया है। इस संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि ये परीक्षाएं छह मार्च से 14 मार्च तक होंगी। प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों के करीब 24 लाख विद्यार्थी 12 हजार से अधिक परीक्षा केंद्र पर शामिल होंगे। दोनों परीक्षाएं सुबह नौ बजे से दोपहर 11.30 बजे तक चलेंगी। विद्यार्थियों को सुबह आठ बजे से ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा।

प्रश्न-पत्र एससीइआरटी और एनसीइआरटी कोर्स के आधार पर बनेंगे -पांचवीं व आठवीं का पहला पेपर प्रथम भाषा- हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व मराठी का होगा। इस बार हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषा का प्रश्नपत्र एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों पाठ्यक्रमों के आधार पर तैयार किए गए हैं।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी जयश्री जैन द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स 13, प्रेस कॉम्प्लेक्स ए.बी. रोड इंदौर से मुद्रित एवं 22, प्रेस काम्पलेक्स, प्रेस हाऊस, ए.बी. रोड इंदौर 452008 से प्रकाशित। प्रधान संपादक- डॉ. राजेश जैन, मो. 9425322301 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)